संख्या:27/2020 /833 / सत्रह-म-2020-6-9 (273) /2016

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिंनाक 18अगस्त, 2020

विषय वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत मछुआ आवास निर्माण परियोजना में अनुसूचित जनजाति मद में रू0 62.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 818 /नि0शा0/ वि0स्वी0/एस0सी0एस0टी0/20-21,दिनांक 15.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति मद में 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु कुल रू0 62.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-12012/27/2009-एफवाई (डब्ल्यू0यू0) दिनांक 06.12.2020 द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 100 मछुआ आवासों निर्माण एवं 03 प्रतिशत केन्द्रांश के प्रशासनिक व्यय को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 74.16 लाख का केन्द्रांश अवमुक्त किया गया था, किन्तु वर्ष 2019-20 में आय-व्ययक में इस मद में बजट व्यवस्था न हो पाने के कारण वर्ष 2019-20 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत नहीं की जा सकी। ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत उक्त निर्गत/अप्रयुक्त केन्द्रांश को भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या-जे-18001/1/2017-एफवाई दिनांक 23.04.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय करने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत आय-व्ययक में रू0 105.60 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 25 जून,2020 द्वारा रू0 43.20 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है,जिसके फलस्वरूप प्रश्नगत मद में 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु रू0 62.40 लाख की बजट धनराशि उपलब्ध है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध बजट धनराशि की सीमान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रांश रू0 37.44 लाख तथा मैंचिंग राज्यांश रू0 24.96 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 62.40 लाख (रू0 बासठ लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्नक-1 की तालिकानुसार श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज''योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश/ गाइड लाइन्स, शासनादेश सं0-18/2017/1128/ सत्रह-म-2017-6-9 (333)/2016 दिनांक 07 जुलाई, 2017 व शासनादेश सं0-02/2018/ 2236/सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश/ गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर /बैंक में जमा नही किया जायेगा ।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/ कार्यक्रम में पूर्व में इस मद में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि प्राप्त नही हुई है ।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020,पत्रसंख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/ 2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं पत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/ 2020-231/2020,दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों/ प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व अद्यतन निर्धारित प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 -लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन- 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101- ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (के060/रा040/ के0+रा0) 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020,दिनांक 24.03.2020,पत्र संख्या-4/ 2020/बी-1-192/ दस-2020-231/ 2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक11.04.2020 एवं पत्र संख्या-6/2020/ बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

6-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-610/ ई-1-दस-2020, दिनांक 14 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक- यथोक्त।</u>

भवदीय,

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

संख्या :27/2020 / 833(1)/सत्रह-म- 2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
6- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

(शासनादेश संख्या:27/2020 /833/सत्रह-म-2020-6-9(273)/ 2016 दिनांक 18अगस्त,2020)

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मछुआ आवासों की संख्या	निर्गत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)		
			केन्द्रांश (60 प्रतिशत)	राज्यांश (40 प्रतिशत)	योग
1	लखीमपुरखीरी	20	14.40	9.60	24.00
2	सोनभद्र	20	14.40	9.60	24.00
3	बलरामपुर	3	2.16	1.44	3.60
4	बहराइच	3	2.16	1.44	3.60
5	श्रावस्ती	3	2.16	1.44	3.60
6	ललितपुर	3	2.16	1.44	3.60
	कुल योग -	**52**	**37.44**	**24.96**	**62.40**

(रूपया बासठ लाख चालीस हजार मात्र)

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।